

गाचीबौली हैदराबाद में गांजा खरीदने पर १५ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

(हैदराबाद से विशेष संवाददाता)
हैदराबाद के गाचीबौली क्षेत्र में इस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने १५ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को गांजा खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि ये सभी युवक देश की जानी-मानी आईटी कंपनियों में कार्यरत हैं। पुलिस के अनुसार, इन इंजीनियरों ने ड्रग तस्करी से संपर्क कर नियमित रूप से गांजा खरीदा था। खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारियां शहर में नशाखोरी पर काबू पाने के लिए चलाई जा रही विशेष मुहिम का हिस्सा हैं। साथ ही, पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गिरोह के कई सदस्यों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
यह घटना न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि यह देश के शिक्षित और युवा वर्ग में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर एक बड़ा सवालिया

निशान भी है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे प्रतिभाशाली युवाओं का नशे जैसी सामाजिक बुराई में लिप्त होना हमारे सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक मूल्यों के गिरते स्तर को दर्शाता है। ऐसे में माता-पिता, शैक्षणिक संस्थान और कॉर्पोरेट कंपनियों को मिलकर नशे के खिलाफ एक सशक्त और प्रभावी अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं को इस गुमराह रास्ते से बचाया जा सके।

शुभ बराबर शुभ शराबी। मधुराला से कमाई में कया खराबी।

राज्य में ३२८ शराब बिक्री लाइसेंसों की सौगात



- रिपोर्ट: जमीर काज़ी मुंबई, १३ जुलाई:
राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले ५० वर्षों से स्थगित शराब बिक्री लाइसेंसों पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत जल्द ही ३२८ नए वाइन शॉप (शराब दुकानों) के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही विदेशी शराब निर्माण लाइसेंस देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक समिति का

गठन किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये ३२८ नए लाइसेंस सीधे दुकानों को नहीं, बल्कि कंपनियों को दिए जाएंगे। हर कंपनी को ८ लाइसेंस मिलेंगे और इन्हें किराये पर देने की अनुमति भी होगी। इन लाइसेंसों के वितरण के लिए बनाई जा रही समिति में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल होंगे। लेकिन शराब निर्माण कंपनी 'कैपोव्हिटेज' के संचालक जय पवार होने के कारण हितसंबंधों का मुद्दा

उठाया जा सकता है, ऐसा आरोप विपक्ष ने लगाया है।
राज्य में ३२८ नए शराब बिक्री लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ये लाइसेंस दुकानों को नहीं, बल्कि कंपनियों को दिए जाएंगे। प्रत्येक कंपनी को ८ शराब बिक्री लाइसेंस मिलेंगे।
राज्य पर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज है। वहीं विधानसभा चुनावों में 'गेम चेंजर' मानी गई 'लाडकी बहन योजना' के लिए निधि जुटाने हेतु अन्य विभागों की राशि को

स्थानांतरित किया जा रहा है। इस कारण संबंधित मंत्रियों द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। इसलिए सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने शुरू किए हैं। इसी नीति का एक हिस्सा वाइन शॉप के लिए लाइसेंस जारी करने का यह निर्णय भी है।
राज्य में पुराने शराब बिक्री लाइसेंस की कीमत १० करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जबकि नया लाइसेंस लेने के लिए कंपनियों को राज्य सरकार

को १ करोड़ रुपये चुकाने होंगे। विदेशी शराब निर्माण के लाइसेंस देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में, जो राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के मंत्री भी हैं, एक समिति का गठन किया गया है।
सरकार की इस नीति को लेकर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के मुख्य प्रवक्ता व विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा, लाडकी बहनों के नाम पर उनके परिवारों को बर्बाद

करने का काम शुरू हो गया है। इस सरकार को सत्ता का घमंड है और बहनों को पैसा देने के लिए उनके पतियों और भाइयों को शराबी बनाया जा रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया, महाराष्ट्र संतों और वकीलों की भूमि है या शराबियों की? ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि एक ही परिवार को ७-८ शराब बिक्री लाइसेंस दिए गए हैं और यह वितरण सिर्फ खास लोगों को किया जा रहा है।

बीड नगर परिषद में अंधेरा कायम, घंटा गाड़ी बंद-शहर बना कचरे का ढेर कलेक्टर कि तरफ आंखें।



बीड / संवाददाता:
अगर आप सड़क पर चलते समय हर कुछ कदम पर गड्ढे, उबलती नालियां, हर गली में कचरे का ढेर, और झुंड में घूमते कुत्ते देखें
समझ लीजिए - आप बीड शहर में हैं।
यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि बीड नगर परिषद की हकीकत है, जिसे अखबारों ने सालों तक लिखा और ना सिस्टम बदला ना जिम्मेदार जागी

स्थिति यह है कि नगर परिषद के पास अब डीजल तक के पैसे नहीं बचे।
घंटा गाड़ी (कचरा उठाने वाली गाड़ी) बंद है, और शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है।
वहीं, जनप्रतिनिधि अपने-अपने नेता, अपना बजट, अपनी सड़क और अपना पेट भरने में व्यस्त हैं। एक शहर जहां नागरिक सांस लेना भी मुश्किल समझें वहां जनसेवक नहीं, जवाबदेही चाहिए।
नगर परिषद की यह लापरवाही स्वास्थ्य

संकट को न्योता दे रही है - मच्छर, गंदगी, कुत्ते, बदबू और अब बीमारियों की आहट भी। बीड की सताई हुई जनता अब जिलाधिकारी से गुहार लगा रही है कि वे स्वयं साफ-सफाई अभियान की निगरानी करें, इससे पहले कि शहर किसी महामारी की चपेट में आ जाए।
अब वक्त आ गया है कि 'अपनी गली' और 'अपनी सड़क' की राजनीति छोड़कर पूरे बीड शहर की सुध ली जाए - वरना हालात हाथ से निकल सकते हैं।

शिंदे गुट के पांच मंत्रियों की एसआईटी जांच हो-संजय राउत की मांग

(रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई)
मुंबई, १३ जुलाई:
राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट सहित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के पांच मंत्रियों पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ठाकरे गुट के नेता व सांसद संजय राउत ने एसआईटी या न्यायिक जांच की मांग की है।
संजय राउत ने आरोप लगाया कि संजय राठोड़, संदिपान भुमरे, संजय शिरसाट, उदय सामंत और योगेश कदम ने भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर जनसेवा का विश्वास तोड़ा है। कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया था, जिसमें वे बनियान पहने बिस्तर पर नजर आ रहे हैं और पास में नकदी से भरा बैग और कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को लेकर सभी स्तरों पर आलोचना शुरू हो गई थी, जिसके बाद मंत्री शिरसाट ने इसे मॉर्फ किया गया वीडियो बताते हुए संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात कही। इस पर जवाब देते हुए राउत ने कहा कि यह तथ्य करना फॉरेंसिक लैब का काम है कि वीडियो असली है या नकली। उन्होंने कहा,
मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और एक समाचार पत्र का संपादक भी हूं। भ्रष्टाचार को उजागर करना मेरा कर्तव्य है। मैं मानहानि के दावे से नहीं डरता, पहले भी कई ऐसे मामलों का सामना कर चुका हूं।
संजय राउत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इन पांच मंत्रियों की



एसआईटी या न्यायिक जांच की घोषणा करके साहस दिखाएं।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए १२ किलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, जो गर्व की बात है, लेकिन भाजपा इस पर जश्न मनाकर राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। इससे पहले महाराष्ट्र की कई वस्तुओं को यह दर्जा मिला है। क्या ये किले भाजपा ने बनाए थे? इस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।
धारावी भूमि घोटाले का आरोप
संजय राउत ने धारावी पुनर्विकास योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई को लूटा जा रहा है। मराठी लोगों को यहां से बेदखल किया जा रहा है। धारावी इसका उदाहरण है। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तो इस परियोजना को रोक दिया गया होता। इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है और इसके ज़रिए मुंबई में ज़मीन घोटाला किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार की आशंका है, उन्हें तत्काल रोकना चाहिए था - चाहे वह शक्तिपीठ महामार्ग हो या अन्य कोई योजना, जिन्हें अदानी समूह के हित में बनाया जा रहा है।
संजय राउत ने साफ कहा कि शिंदे गुट के इन पांच मंत्रियों की जांच न हो पाना, भ्रष्टाचार को खुली छूट देने जैसा है, और इसके लिए अब जनता को न्यायिक सच्चाई की दरकार है।

पुस्तक
**समर्पण
सोहळा**

अर्शद शेख लिखित

इस्लाम द अल्टिमेट आर्ट ऑफ लिविंग

आर्किटेक्ट अर्शद शेख
M.Arch., MBA, MSW, MACJ,
BJMC, DBM, PGDHR, LLB, PhD.,

सोमवार 14 जुलै 2025 सायं. 7:30 ते 9.30.

**९ हज हाऊस,
VIP रोड, किले अर्क, छ.संभाजी नगर (औरंगाबाद)**

• प्रमुख वक्ते •

श्री. अशोक वानखेडे
जेष्ठ पत्रकार

• शुभवक्ते •

डॉ. श्रीपाल सबनीस
माजी अध्यक्ष मराठी साहित्य संमेलन

• कार्यक्रमाचे अध्यक्ष •

डॉ. इकबाल मिर्ने
जेष्ठ साहित्यिक आणि रीडोलॉजिस्ट

• संयोजक •

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी गांधीभवन | नुमाईदा कौंसिल
मुस्लीम मराठी साहित्य सांस्कृतिक मंडळ | पीस फौंडेशन, औरंगाबाद
70407901137 | 9326356700 | 8793217135

गुजरात में पांच साल में १७ पुल ढहे, १८० मौतें

हबीब शेख, अहमदाबाद
गुजरात में वडोदरा के पास गंभीर पुल का ढहना, जिसमें १७ लोगों की जान चली गई, राज्य में कोई नई या असामान्य बात नहीं है, क्योंकि पिछले पांच सालों में राज्य में कुल १७ पुल ढह चुके हैं, जिनमें लगभग १८० लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा के पास ढहे पुल की मरम्मत के लिए पास के एक गाँव के सरपंच ने कलेक्टर और तालुक स्तर पर बार-बार अपील की थी, लेकिन सरकार ने एक न सुनी। परिणामस्वरूप १७ लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही, राज्य में केवल पाँच वर्षों में पुल ढहने की १७ घटनाएँ घटीं।



अहमदाबाद का हटीशोर पुल खुलने के कुछ महीनों के भीतर ही ढहने लगा, जिससे अहमदाबाद नगर निगम को इसे बंद करना पड़ा। इस पुल के निर्माण पर ४० करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसे गिराने और फिर से बनाने में ७० करोड़ खर्च करने होंगे। हालाँकि पुल की गारंटी सौ साल के लिए थी, लेकिन यह एक साल के भीतर ही टूटने लगा। यहाँ पहले हुई १३ सबसे भयावह घटनाएँ हैं, जिनमें लगभग १८० लोग मारे गए। हटेश्वर पुल से पहले ममतापुरा में २१-१२-२०२१ को एक पुल का हिस्सा ढह गया, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए। इसके अलावा, मोरबी में हिलवाड़ के पास एक पुल २६-

०८-२०२४ को भारी बारिश के कारण ढह गया। यह बेहद दुखद घटना ३०-१०-२०२२ को मोरबी में ही घटी थी जब एक पुल ढह गया था जिसमें १४१ लोगों की मौत हो गई थी। मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। मरम्मत का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जिसे कोई अनुभव नहीं था। लोग झूला पुल का आनंद लेने गए थे और उनके परिवारों को शव मिले। इसके अलावा, सूत में निर्माणाधीन मेट्रो रेल का एक हिस्सा भी ३०-१०-२०२४ को क्षतिग्रस्त होने के कारण ढह गया। सौभाग्य से, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सामने आई। उसके बाद,

मेहसाणा के अंबेडकर ब्रिज को भी ४-२-२०२४ को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। यह भी अपने निर्माण के कुछ ही समय बाद ढह गया। फिर २७-८-२०२४ को सौराष्ट्र के चोटिला के हिल्यासर गाँव में पुल के साथ भी यही हुआ। गाँव के लोगों ने इसकी मरम्मत के लिए कई शिकायतें कीं, लेकिन निर्दयी प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। पुल ढहने की एक और घटना पालनपुर में हुई जब २३-८-२०२३ को एक ओवरब्रिज ढह गया जिसमें कुछ पैदल यात्री घायल हो गए। इस तरह, पुल ढहने का सिलसिला जारी रहा, जबकि खेड़ा परिसर से बामन गांव तक बना पुल भी ४-१०-२०२३ को ढह गया। इसके बाद ५-७-२०२३ को ओबर नदी पर

धंधोसर के पास एक पुल या सड़क ढह गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। राजकोट में माधार पुल उस समय चर्चा का विषय बन गया जब चौराहे के पास पुल का एक हिस्सा ढह गया और यातायात ठप हो गया। इसके अलावा, कुछ लोग घायल भी हुए। वडोदरा का गंभीर ब्रिज हाल की कई घटनाओं का केंद्र रहा है। पुल के ऊपर से गुजर रहा एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल, एक रिक्षा और एक मिनी-टैम्पो तेज बहाव में बह गए, जिसमें १७ लोगों की मौत हो गई दक्षिण गुजरात के जबली दीहाट में रहने वाले बच्चे वर्षों से स्कूल जाने के लिए समुद्र में तैर रहे हैं, फिर भी २५ वर्षों तक गुजरात पर शासन करने वाली भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को हल नहीं किया है।

डॉ. सैयद ख्वाजा को शशि थरूर के उपन्यासों पर पीएच.डी की उपाधि

अंग्रेजी साहित्य में पीएच.डी पूरी करने पर हर स्तर से मिल रही शुभकामनाएं

बीड (प्रतिनिधि):
बीड के प्रसिद्ध समाजसेवी सैयद ख्वाजा बास को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की ओर से पीएच.डी (डॉक्टरेट) की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत शशि थरूर के चयनित उपन्यासों में व्यंग्य विषय पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, जिसे विश्वविद्यालय ने मान्यता दी है।
उनका यह शोध कार्य विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के अंतर्गत, यूजीसी के २०१६ के नियमानुसार पूर्ण हुआ है। सैयद ख्वाजा ने यह शोध जिला बीड के शिरूर कासर स्थित कालीका देवी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में, डॉ. रमेश ए. लांडगे के मार्गदर्शन में संपन्न किया।



पीएच.डी की यह उपलब्धि प्राप्त करने पर शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और उनके उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य के लिए शुभेच्छाएं प्राप्त हो रही हैं।
प्र शशि थरूर: एक संक्षिप्त परिचय
शशि थरूर एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखक,

राजनेता, पूर्व राजनयिक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे संयुक्त राष्ट्र में उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं। उनके उपन्यास और नॉन-फिक्शन पुस्तकें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर व्यंग्य, शैली और गहराई के साथ लिखी गई हैं। उनकी चर्चित रचनाओं में The Great Indian Novel, Riot, Inglorious Empire, Amja Why I -m a Hindu प्रमुख हैं।
शशि थरूर की लेखनी भारतीय राजनीति, उपनिवेशवाद के प्रभाव और सांस्कृतिक जटिलताओं पर गहरी रोशनी डालती है, जिससे उन्हें आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

(बीड से विशेष संवाददाता)
बीड स्थित मलिया बाँयज़ हाई स्कूल में जरूरतमंद और निर्धन छात्रों के बीच यूनिफॉर्म, जूते और मोज़ों का वितरण किया गया। इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन अंजुमन इशाअत-ए-तालीम की सचिव महतर्मा खान सबीहा बाजी के करकमलों से संपन्न हुआ।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार व लेखकर जावेद पाशा साहब तथा मलिया जूनियर कॉलेज बीड के वाइस प्रिंसिपल मुजाहिद चौउश साहब उपस्थित थे।
इसके अलावा स्कूल के



प्रिंसिपल फैसल चौउश सर, उपप्रधानाध्यापक सिद्दीकी अलहाज सर, और सुपरवाइज़र सैयद मुइनुद्दीन सर भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्र

बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
अपने उद्बोधन में बाजी साहिबा ने छात्रों को प्रेरणादायक बातें बताते हुए कहा कि
दुनियावी शिक्षा और धार्मिक

शिक्षा दोनों ही ज़िंदगी के लिए बेहद अहम हैं।
उन्होंने विशेष रूप से मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर बल देते हुए बच्चों को एक सफल जीवन जीने के गुर बताए।
गौरतलब है कि यूनिफॉर्म वितरण का लक्ष्य ५०० से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें संस्था के ज़िम्मेदारों और स्कूल के सभी शिक्षकों ने दिल से भाग लिया। यह पूरी तरह निशुल्क वितरण बच्चों के भविष्य के प्रति एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

दरगाह नासरजंग इनाम ज़मीन प्रकरण की जाँच कर दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए,

अन्यथा किया जाएगा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन – सैयद सलीम बापू

बीड / संवाददाता :
परली स्थित ऐतिहासिक दरगाह नासरजंग देवस्थान की इनामी ज़मीन से संबंधित प्रकरण में जल्द से जल्द विशेष समिति के माध्यम से जांच कर दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग आंबेडकरी विचार मोर्चा तथा आंबेडकर रिपब्लिकन मोर्चा के मराठवाड़ा अध्यक्ष सैयद सलीम बापू ने की है।
उन्होंने बताया कि परली तहसील के मौजे शिवार क्षेत्र में सर्वे नंबर ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, २४०, २५९, ३०३, ३०४, ३८८, ३९५, ३९८ और ३९९ की कुल

१७८ एकड़ इनामी ज़मीन, दरगाह नासरजंग देवस्थान की धार्मिक संपत्ति है। इन सर्वे नंबरों की ज़मीनों पर अवैध रूप से खरीद-बिक्री की जा रही है। यह कार्य तलाठी, तहसीलदार, उप-पंजीयक, परली नगर परिषद व भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों की साठगांठ से किया गया है।
गलत सर्वे कर पी.टी.आर. और पी.आर. कार्ड भी जारी किए गए हैं।
परली नगर परिषद और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, स्थानीय भू-माफियाओं व



नेताओं से मिलकर द्वितीय श्रेणी की इनामी देवस्थान भूमि को वैध बनाने की साजिश कर रहे हैं। इस ज़मीन पर किसी प्रकार की कानूनी अनुमति लिए बिना अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए बार-बार प्रशासन को निवेदन दिए गए, पर किसी भी अवैध निर्माणकर्ता पर कार्रवाई नहीं हुई है।
सैयद सलीम बापू ने मांग की है कि इस ऐतिहासिक दरगाह की इनाम ज़मीन मामले की विशेष जांच समिति से जांच करवाई जाए और अवैध

खरीद-बिक्री तथा अवैध निर्माण में लिस दोषियों पर वक्फ अधिनियम १९९५ की धारा ५२(१)(अ) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि १६ जुलाई, बुधवार सुबह ११ बजे तक कार्रवाई नहीं की जाती, तो जिलाधिकारी कार्यालय, बीड के समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से बेमियादी आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इस आशय का लिखित निवेदन आंबेडकरी विचार मोर्चा व आंबेडकर रिपब्लिकन मोर्चा की ओर से मराठवाड़ा अध्यक्ष सैयद सलीम बापू द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, बीड को सौंपा गया है।

अजित पवार के जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख का दिल का दौरा पड़ने से निधन

(विशेष प्रतिनिधि, मुंबई)
महाराष्ट्र सरकार के माहिती व जनसंपर्क विभाग (सूचना व जनसंपर्क विभाग) में वरिष्ठ सहायक निदेशक तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार के जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख (उम्र ५५ वर्ष) का शनिवार रात को दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकारिता और सरकारी जनसंपर्क क्षेत्र ने एक शांत, संयमी, संवेदनशील और अध्ययनशील व्यक्तित्व को खो दिया है।
देशमुख पिछले १५ वर्षों से अजित पवार के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अपने संयमित और प्रभावशाली कार्यशैली के चलते उन्होंने प्रशासन और मीडिया के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाई।
उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत 'मुंबई दिनांक' और 'दैनिक सकाट' जैसे मीडिया समूहों से की थी। मीडिया में मिले अनुभव ने उनके शासकीय जनसंपर्क कार्य को पेशेवर और सुव्यवस्थित स्वरूप दिया।
उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और एक बेटा हैं। अंतिम संस्कार सोमवार (दिनांक १४) को दादर स्थित रमशनभूमि में किया जाएगा।

वन्यजीव संरक्षण में अहम योगदान के लिए अज़ीम काज़ी को जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के हाथों सम्मानित किया गया

जलगांव, १३ जुलाई (मुईन काज़ी):
वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और सामाजिक सेवाओं में सक्रिय योगदान देने



वाले जलगांव के सामाजिक कार्यकर्ता अज़ीम काज़ी को आसरा फाउंडेशन, महारून की ओर से हाल ही में एक सम्मान समारोह में जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के हाथों सम्मानित किया गया।
अज़ीम काज़ी हर वर्ष महारून तालाब में

आयोजित होने वाले गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान SWIMMER GROUP (तेराक दल) के साथ मिलकर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। विसर्जन के दौरान जल दुर्घटनाओं से बचाव और आपातकालीन स्थितियों में सहायता के लिए वे स्वयं आगे आकर सेवाएं देते हैं।
इसी प्रतिबद्धता और निःस्वार्थ सेवा भावना को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में फ़ारूक शेख, नाना भाई लाडोंगरी, एडवोकेट बुरहान पीराजादे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

महायुति की सरकार चोरी की देन है, कांग्रेस मुंबई को लुटने नहीं देगी-इमरान प्रतापगढ़ी



(मुंबई से रिपोर्ट: ज़मीर काज़ी)
मुंबई, १३ जुलाई:

महाराष्ट्र में भाजपा युति की सरकार चोरी की चोरी करके बनाई गई है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा राज्य में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन मतों की चोरी करके सरकार बना ली गई। विधानसभा चुनाव में हार का मतलब यह नहीं कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, शाह महाराज, महात्मा फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों की विरासत को छोड़ दिया है – यह कहना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का।
वे मुंबई कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान जिंदाबाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड़, विधायक असलम शेख, अमीन पटेल, पूर्व विधायक मधु चव्हाण, भवर्सिंह राजपुरोहित, जिला अध्यक्ष रवि बावकर, नगरसेवक हाजी बब्बू, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस, महेंद्र मुगेकर, कचरू यादव, निज़ामुद्दीन राईन, मंदार पवार, तारक शाह, जावेद जुनेजा, अवनीश सिंह आदि उपस्थित थे।

मुंबई भाषा नहीं, भावना की नगरी है – इमरान प्रतापगढ़ी
प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि मुंबई में आज भाषा विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि यह शहर देश के हर कोने से आए लोगों को गले लगाता रहा है। इस शहर ने सभी को आश्रय,

रोज़गार और सपनों की उड़ान दी है। यहां किसी की भाषा, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं पूछा गया। भाषा का सम्मान ज़रूरी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन महाराष्ट्र क्रांति की धरती है, यह शिवाजी महाराज, शाह महाराज, महात्मा फुले और डॉ. आंबेडकर की धरती है।
आज कुछ लोग इस भूमि से गंगा-जमुनी तहज़ीब को मिटाना चाहते हैं। इसलिए हमें आगे आकर इस संस्कृति को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में सरकार भाजपा की है, लेकिन संसद में आवाज़ सिर्फ राहुल गांधी की गूंजती है।

भाजपा ने उन्हें 'शहजादा' और 'राजकुमार' कहकर ताना मारा, लेकिन जब उन्होंने एक सादा सफेद टी-शर्ट पहनकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ४००० किमी की पदयात्रा की, तो १० लाख के सूट पहनने वालों के भी पसीने छूट गए। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग सरकार के सामने रखी और सरकार को झुकना पड़ा – यही उनकी ताकत है।

संविधान को खतरा – प्रतापगढ़ी का आरोप
प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज वही संविधान खतरे में है, जिसे आज़ादी के बाद डॉ. आंबेडकर ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बनाकर लागू किया था। उन्होंने याद दिलाया कि २०१४ में नरेंद्र मोदी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेककर प्रवेश किया था, लेकिन २०२४ तक आते-आते संसद को ही बदल

डाला। २०२४ में उन्होंने संविधान को सिर पर रखा था, इसलिए अगला निशाना संविधान है – यह ध्यान रखना होगा।
आज सत्ता में बैठे लोग डरे हुए हैं। वे ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं। जब मुंबई अदानी को बेची जा रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? आने वाली पीढ़ी आपसे यह सवाल पूछेगी। प्रतापगढ़ी ने दो टुक कहा – कांग्रेस न तो मुंबई को लुटने देगी, न संविधान को बदलने देगी।
वर्षा गायकवाड़ का तीखा हमला
सभा में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि डॉ. आंबेडकर द्वारा देश को दिया गया पवित्र संविधान २०१४ से लगातार कुचला जा रहा है। सभी संस्थाओं की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, न्याय व्यवस्था पर भी अब लोगों को संदेह होने लगा है।
भाजपा के नेता लोकसभा चुनाव में खुलेआम संविधान बदलने की बातें कर रहे थे। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार द्वारा लाया गया जनसुरक्षा कानून अदानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डालने के लिए है।
मुंबई की महत्वपूर्ण और कीमती जमीनें अदानी को दी जा रही हैं – धारावी, मोतीलाल नगर, अभ्युदयनगर, मंदर डेयरी, मिटागर की ज़मीन – सब कुछ अदानी को सौंपा जा रहा है, और इसका विरोध न हो इसलिए यह कानून लाया गया है, ऐसा आरोप वर्षा गायकवाड़ ने लगाया।